पटना-दीघा रेललाइन की जगह बननी है फोर लेन सड़क, योजना को लेकर केन्द्र से बात करेंगे पथ निर्माण मंत्री

पटना-दीघा सड़क पर राज्य सरकार फिर गंभीर

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना-दीघा फोरलेन सड़क योजना को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार गंभीर हुई है। पथ निर्माण विभाग इसको लेकर केन्द्र सरकार को फिर पत्र लिखेगा। जरूरी हुआ तो विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव खुद केन्द्रीय रोड मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। ऐसे में संचिकाओं में दम तोड़ रही पटना-दीघा रेल लाइन हटाकर वहां सड़क बनाने की योजना के एक बार फिर जमीन पर उतरने के आसार जग गए हैं। तीन साल पहले पटना-दीघा रेल लाइन को हटाकर वहां फोरलेन सड़क बनाने की योजना बनी थी। केन्द्र सरकार ने भी उस समय इस योजना पर सहमति दे दी, लेकिन बाद में रेलवे ने जमीन के बदले उतनी ही कीमत की जमीन की राज्य सरकार से मांग कर दी। वह भी कॉमर्शियल दर से, यानी नौ सौ करोड़ रुपये। रेलवे की यह मांग पूरा करना राज्य सरकार के लिए कठिन है। लिहाजा पथ निर्माण विभाग ने एक साल पहले रेलवे के दावे को भूमि सुधार विभाग को भेजकर चुप्पी साध ली थी। अब फिर से सरकार इसपर गंभीर हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के समय ही यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया था। तब रेलवे बदले में जमीन लेने को तैयार नहीं था। रेलवे की मांग थी कि राज्य सरकार इस जमीन का पैसा दे। इतना ही नहीं रेलवे उन अतिक्रमित भूखंड के लिए भी पैसा मांग रहा था जिनपर अभी पक्का मकान बना लिये गये हैं। लिहाजा मामला अटक गया। बाद में मामले में गति आई तो रेट को लेकर बात बिगड़ गई। रेलवे ने कॉमर्शियल दर की मांग कर दी। वैसे पटना-दीघा रूट रेलवे के लिए लाभकारी नहीं है।

कवायद

- जरूरी हुआ तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगे नंदकिशोर यादव
- रेलवे के कॉमर्शियल दर जमीन की कीमत मांगने से भी अटका मामला

03

साल पहले फोरलेन बनाने की बनी थी योजना

योजना के बनने से लाभ

- इस जमीन पर फोरलेन सड़क बनने से बोरिंग रोड पर दबाव कम होगा
- दीघा के लिए नई सड़क मिल जाने से आशिना रोड पर भी दबाव घटेगा
- लाइन के आसपास की जमीन का महत्व बढ़ेगा, बाजार विकसित होगा